विधानसभा में आज कई बार विपक्ष ने हंगामा किया

- बजट पर चर्चा के दौरान शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की गोविंद सिंह डोटासरा पर की गई टिप्पणी को लेकर जोरदार हंगामा हुआ
- प्रश्नकाल में शांति धारीवाल के प्रदेश में पन्नाधाय जीवन अमृत योजना के बारे में किए सवाल का सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने जवाब दिया तो धारीवाल उत्तर से संतुष्ट नहीं हुए और कांग्रेस सदस्यों ने नारेबाजी की
- शून्यकाल में बोलते हुए नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने बजट की योजनाओं का मुद्दा उठाया और प्रदेश की भजनलाल सरकार पर कांग्रेस के विधायकों की अनदेखी करने का आरोप लगाकर हंगामा मचाया

जयपुर, (वि.सं.)। विधानसभा में सोमवार को विपक्ष के सदस्यों ने विभिन्न मुद्दों को लेकर जोरदार हंगामा किया।

सदन में सोमवार को प्रश्नकाल, शून्यकाल और उसके बाद भी विपक्ष के सदस्यों ने हंगामा किया। शून्यकाल के बाद जब बजट पर चर्चा के दौरान कांग्रेस सदस्य गोविंद सिंह डोटासरा बोल रहे थे तब शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की डोटासरा पर की गई टिप्पणी को लेकर जोरदार हंगामा हुआ। डोटासरा जब बोल रहे थे तो आखिर में टोकते हुए दिलावर ने कहा कि डोटासराजी आप तो जेल जाने की तैयारी करो। इस पर विपक्ष के सदस्यों के ऐतराज जताते हुए बोलने से सदन में शोरगुल और हंगामा हुआ। इस पर जूली ने कहा कि मंत्री कानून से ऊपर हैं क्या, मंत्री के पास कहां जेल भेजने के अधिकार हो गए। हंगामा बढ़ते देख अध्यक्ष ने शांत होने के लिए कहा लेकिन विपक्ष शांत नहीं हुआ। इस दौरान संसदीय कार्यमंत्री जोगाराम पटेल भी बोले। बाद में देवनानी ने कहा कि जो भी असंसदीय शब्द हैं, उन्हें हटा दिया जाएगा। इसके बाद मामला शांत हो गया।

इससे पहले प्रश्नकाल के समाप्त होने से कुछ समय पहले जब पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस सदस्य शांति धारीवाल के प्रदेश में पन्नाधाय जीवन अमृत योजना के बारे में किए सवाल एवं पूरक प्रश्न का सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने जवाब दिया लेकिन धारीवाल उत्तर से संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने कहा कि मंत्री यह बताये कि योजना में गत वर्ष कितनी राशि खर्च हुई हैं, जिसका जवाब नहीं मिला हैं। इस पर विपक्ष के अन्य सदस्य भी खड़े हो गए और जवाब दो, जवाब दो नारेबाजी शुरु कर दी। जिससे सदन में हंगामा हुआ। दो मिनट बाद प्रश्नकाल समाप्त होने पर हंगामा शांत हो गया।

इसके बाद शून्यकाल में स्थगन प्रस्ताव के तहत बोलते हुए नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने बजट की योजनाओं का मुद्दा उठाया और प्रदेश की भजनलाल सरकार पर कांग्रेस के विधायकों की अनदेखी करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा बाकायदा एक पत्र जारी कर जनप्रतिनिधियों से प्रस्ताव मांगे गए, जनता ने जिन्हें नकार दिया और जो चुनाव हार गए उनके प्रस्ताव शामिल कर नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नियम के अनुसार सड़क कार्यों का बजट बनाने से पहले राज्य सरकार हर क्षेत्र के स्थानीय प्रतिनिधि से सुझाव मांगती है और फिर जरूरत के अनुसार उन्हें बजट में शामिल करती है लेकिन भजनलाल सरकार ने कांग्रेस विधायकों से कोई सुझाव नहीं मांगे। उनकी बजाय उसी क्षेत्र के हारे हुए भाजपा प्रत्याशियों से सुझाव लेकर बजट की योजनाएं बनाई गईं। ऐसी पहली बार हुआ है और यह नियमों का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि बजट भी 10 करोड रुपए से घटाकर पांच करोड रुपए कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के जो चुनाव हार गए हैं उनसे विकास कार्यों की राय ली जा रही है ऐसे में चुने हुए जनप्रतिनिधि कहां जाएंगे।

जूली बोले विधानसभा का सबसे बड़ा सदस्य विधायक होता है जिसे स्थानीय जनता चुनती है। लेकिन पहली बार विधायक की सलाह न लेकर एक हारे हुए प्रत्याशी की सलाह से सड़क निर्माण की बजट योजनाएं बनाई गई हैं। यह सरकार क्या एक हारे हुए नेता को जनप्रतिनिधि मानती है। उन्होंने कहा कि इस सरकार को पाबंद कर देना चाहिए। उन्होंने कहा वह इस मामले में अध्यक्ष का संरक्षण चाहते हैं कि वे इस पर जवाब मांगे और इन योजनाओं को पास करने से पहले मतदान कराएं। इस दौरान जूली ने सरकार से पूछा कि सरकार बजट योजनाओं पर मतदान कराने से क्यों डर रही है। अध्यक्षजी आप मतदान क्यों नहीं करवा रहे हैं।

सोमवार को भी भादरा चुनाव और शिक्षा मंत्री दिलावर के डीएनए के बयान की गूंज सदन में गूंजती रही। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और विपक्ष ने भादरा चुनाव को लेकर दो सप्ताह बीत जाने के बाद भी सरकार के अस्पष्ट रुख के प्रति जमकर नारेबाजी की। विपक्ष ने इस पूरे मामले में संलिप्त अधिकारियों पर कार्रवाई करने की मांग की।उन्होंने कहा कि यह संविधान खत्म करने की साजिश है, इस दौरान सदन में न्याय दो-न्याय दो के नारे गूंजते रहे, इधर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के आदिवासियों के खिलाफ दिए गए बयान के बाद अभी तक माफी नहीं मांगे जाने से भी बिफरा विपक्ष सदन में हंगामा करता दिखाई दिया।

'प्रस्ताव पर बस्सी में नई ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गठन होंगे'

जयपुर, (वि.सं.)। सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार ने सोमवार को विधानसभा में आश्वस्त किया कि बस्सी विधानसभा क्षेत्र में जिला स्तरीय कमेटी की अनुशंसा सहित प्रस्ताव प्राप्त होने पर नियमानुसार नई ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गठन की कार्यवाही की जाएगी।

कुमार प्रश्नकाल में विधायक लक्ष्मण के प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने बस्सी में गोदाम निर्माण से शेष रही 22 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में भी प्रस्ताव मंगवाकर गोदाम निर्माण करवाने का भी आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि विधानसभा क्षेत्र बस्सी में ग्राम सेवा सहकारी समिति से वंचित सात ग्राम पंचायत मुख्यालयों में नई ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गठन के लिए जिला कलक्टर से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

विधायकों को वीडियो अंश अब अगले दिन मिल सकेंगे

- विधानसभा अध्यक्ष वसुदेव देवनानी की पहल पर यह व्यवस्था पहली बार लागू हुई है
- वीडियो अंश ऑनलाइन भी उपलब्ध होंगे

जयपुर। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा है कि सत्र के दौरान सदन में विधायकों के उद्बोधनों के वीडियो अंश अब अगले दिन ऑनलाइन उपलब्ध कराये जायेंगे। राजस्थान विधानसभा के इतिहास में वीडियो अंश पहली बार ऑनलाइन उपलब्ध कराये जायेंगे।

विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की पहल पर यह व्यवस्था राजस्थान विधानसभा में पहली बार लागू हुई है। अध्यक्ष देवनानी ने सोलहवीं विधानसभा के दूसरे सत्र में इस नवाचार की जानकारी देते हुए सदन को अवगत कराया कि इस पहल से विधायकों के साथ ही उनके क्षेत्र के लोग व प्रदेशवासी क्षेत्रीय विधायक की सदन में सक्रियता से परिचित हो सकेंगे।

देवनानी ने बताया कि विधानसभा सत्र के दौरान सदन की कार्यवाही की ऑनलाइन व्यवस्था है। सदन में विधायकों के उदबोधन के दौरान वीडियो अंश दिये जाने की व्यवस्था भी है। अभी तक विधायकों को उनके उदबोधनों के वीडियो अंश सत्र समाप्ति के पश्चात उपलब्ध कराये जाते थे। अध्यक्ष देवनानी ने बताया कि वर्तमान में बदलते परिवेश में डिजिटल मीडिया के महत्व को देखते हुए सदन में संबंधित विधायकों के उदबोधन के अंश अब एक दिन पश्चात उपलब्ध करवाये जायेंगे ताकि जन-जन को विधायकों की सदन में सक्रियता की जानकारी मिल सकें। देवनानी ने यह निर्णय वर्तमान की आवश्यकता को देखते हुए लिया है।

विधानसभा में अध्यक्ष देवनानी की सोच और उनकी पहल से यह सम्भव हुआ है। देवनानी ने बताया कि विधायकों को उनके द्वारा सदन में दिये जाने वाले उदबोधनों के वीडियों अंश जो वर्तमान में सत्र की समाप्ति पर पैन ड्राइव के माध्यम से उपलब्ध कराये जाते थे, अब उन्हें राजस्थान विधानसभा की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवश्यक नियमानुकुल एडिटिंग करके एक दिवस पश्चात उपलब्ध करवाये जायेंगे। उन्होंने बताया कि वीडियो अंश उपलब्ध कराये जाने वाली यह नवीन व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है।

'फर्जी पदाधिकारी बन गैरकानूनी काम करने वालों पर कार्रवाही होगी'

जयपुर, (वि.सं.)। सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार ने सोमवार को विधानसभा में कहा कि कूटरचित दस्तावेजों से संस्थाओं के फर्जी पदाधिकारी बनकर बंद पड़ी संस्थाओं की भूमि पर कब्जा करने जैसे गैरकानूनी कार्य करने वाले दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

कुमार शून्यकाल में विधायक जेठानंद व्यास द्वारा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से इस सम्बन्ध में उठाये गए मामले पर जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रकरण संज्ञान में लाये जाने पर कमेटी बनाकर अथवा जांच एजेंसी के माध्यम से जांच करवाकर दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने बताया कि वर्तमान में राज्य में 2 लाख 70 हजार 257 संस्थाएं पंजीकृत हैं। राजस्थान सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 के तहत संस्थाओं का पंजीकरण किया जाता है। अधिनियम की धारा-4 के अंतर्गत पंजीकृत संस्थाओं को प्रतिवर्ष रजिस्ट्रार, संस्थाएं कार्यालय में वार्षिक सूची दाखिल करनी होती है। संस्था द्वारा उपलब्ध कराई गई पदाधिकारियों की सूची में से ही किसी के आवेदन करने पर मूल दस्तावेजों की प्रति उपलब्ध कराई जाती है।

बजट में शिव विधानसभा का नाम तक नहीं : भाटी

जयपुर, (वि.सं.)। शिव विधानसभा क्षेत्र के निर्दलीय विधायक रविन्द सिंह भाटी ने कहा कि पूरे बजट में शिव विधानसभा क्षेत्र को कुछ नहीं मिला है। बजट में एक जगह भी शिव क्षेत्र का नाम तक नहीं है। क्षेत्र की जनता ने मुझसे पूछा कि बजट में कुछ नहीं दिया गया। मैंने कहा कि शायद मैंने लोकसभा चुनाव लड़ा, इसलिए कुछ नहीं मिला। सरकार ने शिव क्षेत्र के लोगों के अधिकार और मूलभूत सुविधाओं पर यह कुठाराघात है।

'ई-मित्र के कारण वृद्धजन की पेंशन रुकने पर कार्रवाई होगी'

जयपुर, (वि.सं.)। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने सोमवार को विधानसभा में ई-मित्र संचालकों द्वारा गलत सत्यापन होने के कारण वृद्धजन पेंशनरों का पेंशन से वंचित रह जाना गंभीर मामला बताते हुए आश्वस्त किया कि ऐसे ई-मित्र संचालकों के विरुद्ध जांच कर समुचित कार्रवाई की जाएगी तथा दोषी पाए जाने पर उनका लाइसेंस भी निरस्त किया जाएगा।

गहलोत ने प्रश्नकाल में विधायक जसवंत सिंह यादव के प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि वृद्धजन पेंशनर्स को सही समय पर पेंशन का लाभ देने के लिए विभाग द्वारा हरसंभव प्रयास किया जा रहा है। मोबाइल पर बायोमैट्रिक सत्यापन नहीं हो पाने की स्थिति में संबंधित स्वीकृतिकर्ता अधिकारी के मोबाइल पर ओटीपी उपलब्ध करवाकर पेंशनर का वार्षिक भौतिक सत्यापन कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि शहरी क्षेत्र के लिए उपखण्ड अधिकारी तथा ग्रामीण क्षेत्र के लिए खण्ड विकास अधिकारी स्वीकृतिकर्ता अधिकारी है।

उन्होंने कहा कि पेंशन से वंचित बुजुर्गों के पेंशन संबंधी आक्षेपों की पूर्ति के लिए ग्रामसेवक को प्रत्येक वृद्धजन तक पहुंचने के लिए बीडीओ के माध्यम से निर्देशित किया जाएगा ताकि कोई भी वृद्धजन पेंशन से वंचित नहीं रहे। इसके अतिरिक्त शारीरिक रूप से अक्षम वृद्धजनों के निवास पर ई-मित्र संचालक को भेजकर भी पेंशन का सत्यापन कराया जा सकता है।

'वर्तमान में होमगार्डों को दिया जा रहा है विराम भत्ता'

जयपुर, (वि.सं.)। गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने सोमवार को विधानसभा में कहा कि राज्य सरकार द्वारा वर्तमान में होमगार्ड स्वयं सेवकों को विराम भत्ता दिया जा रहा है।

खराड़ी प्रश्नकाल में पूरक विधायक अमृतलाल मीणा के प्रश्न पर जवाब दे रहे थे। उन्होंने बताया कि गत सरकार द्वारा छह मई 2022 को विराम भत्ता दिया जाना स्थगित कर दिया गया था लेकिन अब गत 27 फरवरी से यह भत्ता नियमानुसार फिर देना शुरु कर दिया गया है।

अपशिष्ट का उचित निस्तारण नहीं करने पर औद्योगिक इकाइयों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई होगी : संजय शर्मा

जयपुर, (वि.सं.)। पर्यावरण राज्य मंत्री संजय शर्मा ने सोमवार को राज्य विधानसभा में कहा कि किसी भी औद्योगिक इकाई द्वारा अपशिष्ट निस्तारण के संबंध में नियमों के विरुद्ध कार्य करने पर उसके खिलाफ कठोर कार्वाई की जाएगी।

शर्मा प्रश्नकाल में विधायक दीप्ति किरण माहेश्वरी के प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने राजसमन्द में मार्बल स्लरी की अवैध डंपिंग का सर्वे कराकर दोषी के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए आश्वस्त किया। उन्होंने कहा कि राजसमंद जिले में संचालित औद्योगिक इकाइयों द्वारा अपशिष्ट का उचित निस्तारण न किया जाना बेहद चिंता का विषय है।

उन्होंने सदन में चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि किसी भी उद्योग को यह छूट नहीं है कि वे औद्योगिक अपशिष्ट के माध्यम से उस क्षेत्र विशेष के जल संसाधन और पर्यावरण को दूषित करें और वहां के निवासियों तथा किसानों को तकलीफ पहुंचाएं। उन्होंने कहा कि राजसमन्द में मार्बल स्लरी का निस्तारण कहीं अन्यत्र न करके निर्धारित डंपिंग यार्ड में ही किया जाना सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन एवं राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अधिकारियों को निर्देशित किया जाएगा।

उन्होंने हिंदुस्तान जिंक औद्योगिक इकाई द्वारा औद्योगिक अपशिष्ट का उचित निस्तारण नहीं किये जाने के सन्दर्भ में सचेत करते हुए कहा कि जिले में संचालित किसी भी औद्योगिक इकाई द्वारा विभाग के नियमों की पलना नहीं किये जाने जाने पर राज्य सरकार इनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने में पीछे नहीं हटेगी।

हिंगौनिया गौशाला के बाड़ों में कीचड़ 6 इंच की मोटाई में जमा हुआ मिला

ग्रेटर महापौर डॉ. सौम्या गुर्जर ने सोमवार सुबह चेयरमैन व पशु प्रबंधन शाखा के अधिकारियों के साथ किया था गौशाला का औचक निरीक्षण

जयपुर (कासं)। हिंगौनिया गौशाला के बाड़ों में 6 इंच से ज्यादा कीचड़ फैला हुआ है। गायों के लिए चारा भी पर्याप्त नहीं है। गंदगी के कारण गौवंश की दुर्दशा होती देखकर महापौर डॉ. सौम्या गुर्जर ने सोमवार सुबह हिंगौनिया गौ-पुनर्वास केन्द्र के प्रभारी डॉ. अशोक मीणा और अक्षयपात्र ट्रस्ट के लोगों को फटकार लगाई। दरअसल महापौर सोमवार सुबह करीब साढ़े 9 बजे अचानक हिंगौनियाा गौशाला पहुंच गई। उनके साथ चेयरमैन अरूण वर्मा, शंकरलाल शर्मा, नरेन्द्र सिंह और उपायुक्त पशु प्रबंधन, प्रभारी चिकित्सक और श्रीकृष्ण-बलराम ट्रस्ट के पदाधिकारी मौजूद थे।

- मेयर ने इस लापरवाही पर जवाब मांगा तो गौ-पुनर्वास केन्द्र के प्रभारी डॉ. अशोक मीणा और गौशाला प्रबंधन बगलें झांकता नजर आया
- महापौर एम.ओ.यू. की शर्तों की पालना नहीं करने पर श्रीकृष्ण-बलराम ट्रस्ट और निगम के डॉ. अशोक मीणा के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए

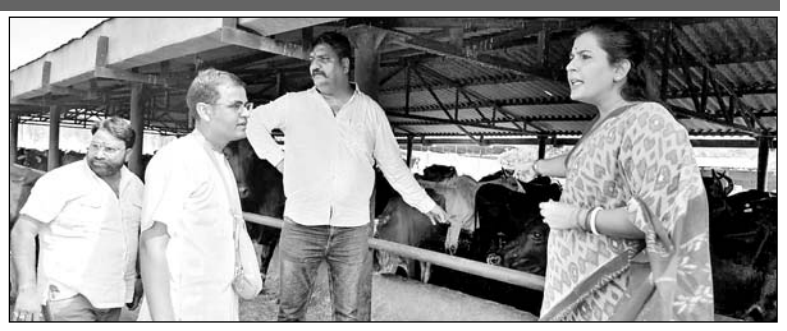

महापौर डॉ. सौम्या गुर्जर ने हिंगौनिया गौ-पुनर्वास केन्द्र का औचक निरीक्षण किया।

महापौर ने गौशाला में गायों के चारे की व्यवस्था, गौवंश के स्वास्थ्य और सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया। इस दौरान गायों के पास ना तो चारा मिला और ना ही बाड़ों साफ-सफाई। मेयर जब गायों के बाड़ों में पहुंची तो वहां पर करीब 6 इंच तक मोटाई कीचड़ और गंदगी जमी मिली। गौवंश को कष्ट में देखकर महापौर का पारा हाई हो गया। उन्होंने इस बारे में हिंगौनिया गौ-पुनर्वास केन्द्र के प्रभारी डॉ. अशोक कुमार मीणा से इस बारे में जवाब मांगा तो वे बगले झांकते नजर आए। यही हाल गौशाला की देखरेख कर रहे बलराम ट्रस्ट के पदाधिकारियों का रहा। मेयर ने गौवंश की दुर्दशा देखते हुए आयुक्त रूकमणि रियाड़ को नोटशीट लिखकर हिंगौनिया गौ-पुनर्वास केन्द्र के प्रभारी चिकित्सक डॉ. अशोक कुमार मीणा के खिलाफ कार्रवाई करने और एम.ओ.यू. की शर्तों की पालना नहीं करने पर बलराम ट्रस्ट के खिलाफ भी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। महापौर ने कहा कि हिंगौनियां गौशाला में गौवंश की अच्छी सेवा के नाम पर जिस अक्षयपात्र ट्रस्ट ने इसकी सार संभाल का जिम्मा लिया था, अब वह एम.ओ.यू. की शर्तों की पालना नहीं कर रहा है।

चोरी और लूटपाट करने वाला शातिर बदमाश गिरफ्तार

जयपुर। मानसरोवर पुलिस ने चोरी और लूट करने वाले एक शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में आरोपी ने बारह से ज्यादा वारदात करना कबूला है। इसके अलावा पुलिस ने आरोपी के साथ एक नाबालिग को भी पकड़ा है। प्रारम्भिक पूछताछ के बाद पुलिस ने आरोपी को बाल सुधार गृह में भेज दिया है।

पुलिस उपायुक्त जयपुर दक्षिण दिगंत आनंद ने बताया कि मानसरोवर थाने में 8 जुलाई को मानसरोवर के अग्रवाल फार्म में रहने वाले रोहित मुटरेजा ने मामला दर्ज करवाया था कि वह गुड़गांव गया हुआ था। इस दौरान रात को उससे घर में चोरी हो गई। सारी वारदात सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गए। सीसीटीवी में 2 लड़के घर का सामान चोरी करते दिखाई दे रहे हैं। बदमाशों ने घर में रखे 30 से 40 हजार कैश, सोने के 2 झुमके, चांदी के कड़े, कपड़े और घर का अन्य सामान ले गए।

पुलिस ने मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज चैक किए। इस पर पुलिस के हाथ आरोपी का फोटो लग गया। इस पर टीम ने मुखबिर की मदद से गंगापुर सिटी के बालाघाट में रहने वाले आरोपी अतुल गुर्जर को गिरफ्तार किया है। जो जयपुर में मुहाना में हनुमान विहार इस्कॉन रोड़ पर रह रहा था। आरोपी को पुलिस ने कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया है। इसके अलावा एक बाल अपचारी को भी निरुद्ध किया गया।

राजस्थान में जल जीवन मिशन के कार्यों की गति बढ़ाएं: केंद्रीय जल शक्ति मंत्री

मंत्री सी.आर.पाटिल ने आश्वस्त किया कि, "जल जीवन मिशन" में केन्द्र सरकार की तरफ से हर संभव सहयोग किया जाएगा

जयपुर, (कासं)। केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर.पाटिल की अध्यक्षता में दिल्ली में सोमवार को हुई जल जीवन मिशन की बैठक में राजस्थान के जलदाय मंत्री कन्हैयालाल व वरिष्ठ अफसर भी शामिल हुए।

केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर.पाटिल की अध्यक्षता में दिल्ली में सोमवार को हुई जल जीवन मिशन की बैठक में राजस्थान के जलदाय मंत्री कन्हैयालाल व वरिष्ठ अफसर भी शामिल हुए।

बैठक में जल शक्ति मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार जल जीवन मिशन के तहत "हर घर जल" संकल्प को साकार करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा हैं, ताकि राजस्थान के हर गाँव में शुद्ध पानी पहुँच सके। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को जल जीवन मिशन कार्यक्रम में हर संभव सहयोग किया जाएगा। साथ ही जल जीवन मिशन के तहत प्रदेश में जो कार्य किए जा रहे हैं, उनकी गति बढ़ाये जाने की जरूरत है। राजस्थान के जलदाय मंत्री कन्हैयालाल ने प्रदेश में जल जीवन मिशन के तहत जो कार्य चल रहे हैं उनके बारे में विस्तार पूर्वक अवगत कराया। साथ ही प्रदेश में कार्यक्रम के तहत जो समस्या आ रही है उसके बारे में भी अवगत करते हुए बताया कि प्रदेश में जल जीवन मिशन की अवधि जो मार्च 2024 को समाप्त हो गयी है, उसकी समयावधि बढ़ाए जाने की मांग की गई। केंद्रीय जल सचिव विनी महाजन ने कहा कि राजस्थान में जल जीवन मिशन के तहत जो कार्य किया जा रहे हैं उनकी गति बढ़ाई जाए। साथ ही जिन गांवों में शत-प्रतिशत कार्य कर दिया गया, उन गांवों का सर्टिफिकेशन ग्राम सभा के माध्यम से शीघ्र कराया जाना सुनिश्चित करावे। नल-जल मित्र का सलेक्शन एवं प्रशिक्षण के संबंध में शीघ्र पूर्ण कार्रवाई की जाए। जल जीवन मिशन के तहत पेयजल की जांच समय-समय पर की जाए। उन्होंने कहा कि घरेलू क्रियाशील कनेक्शन चालू रहे इसका समय-समय पर फील्ड के माध्यम से सूचना लेते रहें। इस योजना के तहत जहां भी शिकायते प्राप्त होती हैं, उनका तुरंत समाधान किया जाए। हर जल स्त्रोत पर वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाना सुनिश्चित करें, जिससे कि भूजल रिचार्ज होता रहे। जलदाय सचिव डॉ. समित शर्मा ने बैठक में कहा कि जल जीवन मिशन कार्यक्रम के तहत जो कार्य आदेश दिए गए हैं उनकी समय अवधि एवं कई कार्य ऐसे हैं, जो अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाए, उनकी भी समय अवधि बढ़ाए जाने और जल जीवन मिशन कार्यक्रम की वार्षिक कार्य योजना 2024-25 के अनुमोदन किए जाने का अनुरोध किया। बैठक में केंद्रीय जल शक्ति (राज्य मंत्री) राज भूषण चौधरी, केंद्रीय अतिरिक्त जल सचिव चंद्र भूषण कुमार, प्रदेश के जल जीवन मिशन के एम.डी. बचनेश अग्रवाल समेत कई अधिकारी मौजूद थे।

गोपालपुरा मोड से त्रिवेणी पुलिया तक करीब 3 किलोमीटर क्षेत्र में हटाए 150 अतिक्रमण

जयपुर। जयपुर विकास प्राधिकरण ने सामूहिक अभियान चलाकर सोमवार को गोपालपुरा मोड से त्रिवेणी पुलिया तक सड़क के दोनो तरफ करीब 3 कि.मी. के दायरे में 150 अतिक्रमणों को जेसीबी मशीन की मदद से ध्वस्त किया।

जयपुर विकास आयुक्त मंजू राजपाल ने बताया कि नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने गत 9 जुलाई को जयपुर शहर में मुख्य सड़कों और सेक्टर रोड पर अवैध कब्जे और अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए थे। ताकि शहर में यातायात आवागमन में लोगों को बेवजह कोई परेशानी नहीं उठानी पड़े। यूडीएच मंत्री के निर्देशानुसार प्रवर्तन विंग के मुखिया महेन्द्र कुमार शर्मा के नेतृत्व में टीम ने गोपालपुरा मोड से त्रिवेणी पुलिया तक करीब 3 किलोमीटर दूरी में 150 कच्चे-पक्के अतिक्रमण हटाए है। महेन्द्र शर्मा ने बताया कि कार्रवाई के दौरान मकान-दुकानों के बाहर अत्यधिक लम्बाई में बने चबूतरे, सीढ़ियां, रैम्प और बाउण्ड्रीवाल को ध्वस्त किया। इसके साथ ही सड़क पर यातायात जाम करने वाले अवैध थड़ी-ठेले, होर्डिंग-साइन बोर्ड को भी हटाया गया।

'भ्रष्टाचारी पकड़ने के लिए व्यूह रचना की जरूरत'

जयपुर। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को कोई ऐसी व्यूह रचना बनाने की आवश्यकता है कि एक बार कोई पकड़ा जाए तो फिर कानूनन वह किसी स्तर पर छूटे नहीं।

राज्यपाल ने यह बात सोमवार को बिड़ला ऑडिटोरियम में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के स्थापना दिवस पर संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि कहीं किसी स्तर पर भ्रष्टाचार होना पाया जाता है तो त्वरित उसकी शिकायत की जाए। ए.सी.बी. भी पुख्ता सबूत इस तरह से जुटाएं जाएं कि अपराधी को साक्ष्य के अभाव का लाभ नहीं मिले। उन्होंने भ्रष्टाचार से जुड़े विभिन्न प्रकरणों की चर्चा करते हुए कहा कि सार्वजनिक सेवा में अपने पद का, रूतबे का और अधिकारी के रूप में प्राप्त जानकारी का दुरुपयोग किया जाता है तो वह भी भ्रष्ट आचरण में ही आएगा।

इस अवसर पर मुख्य सचिव सुधाश पंत ने कहा कि अधिकारियों को निर्णय तुरंत लेना चाहिए और तत्काल उसके क्रियान्वयन को भी सुनिश्चित किया जाए। इससे भ्रष्टाचार को काफी हद तक होने से रोका जा सकता है। उन्होंने केंद्र सरकार की लाभान्वित को सीधे राशि ट्रांसफर योजना की चर्चा करते हुए कहा कि इससे 22 हजार करोड़ की केंद्र को और 5 हजार करोड़ की बचत राज्य सरकार को हुई है। उन्होंने फाइल निपटाने के स्तर को कम किए जाने पर भी जोर दिया। पंत ने कहा है कि फाइल को रोककर रखना भ्रष्टाचार का एक मुख्य कारण हो सकता है। मैं एक फाइल का डिस्पोजल 24 मिनट में कर देता हूं। उन्होंने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री के स्तर पर यह निर्णय लिया गया की राज्य में सरकारी कार्य में देरी नहीं हो। इसके लिए फाइल निपटान के समय को सभी स्तरों पर कम किया गया है। उन्होंने कहा कि सभी अपने कार्य को प्रभावी ढंग से अंजाम दे। स्वयं ईमानदार रहे और ईमानदारी को नीचे के स्तर पर सुनिश्चित भी करे। पुलिस महानिदेशक उत्कल रंजन साहू ने कहा कि लगभग सभी जिला मुख्यालयों पर भ्रष्टाचार निरोधक कार्यालय प्रभावी कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी विभागों में कार्यरत अधिकारी और विजिलेंस शाखाएं भ्रष्टाचार मुक्त राज्य में अपनी सहभागिता निभाएं। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक रवि प्रकाश मेहरड़ा ने कहा कि भ्रष्टाचार राष्ट्र और राज्य की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र के बाद राजस्थान में भ्रष्टाचार निरोधी सर्वाधिक कार्यवाही की जाती है। राज्यपाल ने इस अवसर पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा प्रकाशित स्थापना दिवस पोस्टर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाते "भ्रष्टाचार मुक्त समाज निर्माण" का लोकार्पण किया। उन्होंने संविधान की उद्देशिका का वाचन करवाया।

राज्यपाल कलराज मिश्र ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के स्थापना दिवस पर सोमवार को जागरूकता पोस्टर का विमोचन किया।